INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

UPSC – CSE

(संघ लोक सेवा आयोग)

(हिंदी माध्यम)

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु

सत्यमेव जयते

UPSC

भाग – 9

भारत की अर्थव्यवस्था भाग - 1

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**UPSC-CSE (IAS/IPS/IFS) (हिंदी माध्यम)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **संघ लोक सेवा आयोग** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य)**" में पूर्ण संभव मदद करेंगें **/**

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp कीजिए - https://wa.link/6bx90g

Online Order कीजिए - https://shorturl.at/5gSVX

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	अर्थशास्त्र का परिचय • अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र • व्यापक, सूक्ष्म और मेसो अर्थशास्त्र • राजनीतिक, उदारवादी और नव-उदारवादी, केनेसियन, समाजवादी और साम्यवादी, विकास, व्यवहारिक, हरित अर्थशास्त्र	1
2.	भारत की राष्ट्रीय आय • परिचय • आर्थिक विकास :- इसके लाभ और दुष्प्रभाव • जीडीपी और जीएनपी • राष्ट्रीय आय और सकल मूल्य संवर्धन (GVA) • प्रति व्यक्ति आय	9
3	आर्थिक वृद्धि परिचय • विकास के मापदंड • मानव विकास सूचकांक (HDI) • वास्तविक प्रगति संकेतक (GPI) • सामाजिक प्रगति सूचकांक • सकल राष्ट्रीय खुशी (GNH) • खुशी सूचकांक • OECD बेहतर जीवन सूचकांक • हरित जीडीपी • आर्थिक प्रदर्शन और सामाजिक प्रगति के मापदंडों पर आयोग (CMEPSP) • क्रय शक्ति समता (PPP) • बिग मैक सूचकांक	16
4	अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक संरचना • परिचय • भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उनके घटक • औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था क्षेत्र • व्यापार चक्र • विकसित, विकासशील और न्यूनतम विकसित देश • विश्व बैंक वर्गीकरण	21
5	भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधनों का जुटाव, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे • परिचय • भारतीय अर्थव्यवस्था : स्वतंत्रता से पहले • स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था • योजना	24

	• भारत में विकास और रोजगार में प्रमुख मुद्दे • समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे	
6	भारत में आर्थिक योजना • परिचय • भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास • आर्थिक विकास का नेहरू-महालनोबिस मॉडल • आर्थिक सुधार • नीति आयोग	36
7	भारत और निर्माण क्षेत्र	51
8	धन और बैंकिंग	59
9	भारत में बैंकिंग - भाग - 1 • भारत में बैंकिंग का इतिहास और विकास • वित्तीय मध्यस्थ • भारत में बैंक • आरबीआई : उत्पत्ति और विकास	68
10	RBI की मौद्रिक नीति • मौद्रिक नीति के उद्देश्य • मौद्रिक नीति के उपकरण • आरबीआई द्वारा गैर-पारंपरिक मौद्रिक नीति उपकरण • आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य मौद्रिक उपकरण • मौद्रिक नीति के प्रकार	74
11	भारत में बैंकिंग – भाग - 2 • वाणिज्यिक बैंक • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक • बैंकों का राष्ट्रीयकरण • बैंकों का विलय / एकीकरण • निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) • लघु वित्त बैंक (SFB), भुगतान बैंक • इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) • सहकारी बैंक • अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान • अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI) • भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM) • नाबार्ड (NABARD) • भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) • बैंकिंग क्षेत्र में सुधार • पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR)	82

	• बैंकों की पूंजी का वर्गीकरण	
12	समकालीन बैंकिंग क्षेत्र के मुद्दे • एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्ति) और तनावग्रस्त परिसंपत्तियाँ • विशेष उल्लेख खाते (SMA) • परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (ARCs) • परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (AQR) • प्रोजेक्ट सक्षम • एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) में सुधार • पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला • यस बैंक संकट • पीएमसी बैंक संकट	112
13	वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति	121
14	आर्थिक सर्वेक्षण	128
15	बजट	135
16	भारत में कराधान • कराधान शक्ति का वितरण • करों के प्रकार • जीएसटी • राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (नापा) • वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) • संघ से राज्यों को कर हस्तांतरण • काला धन • भारत में खराब कर : जीडीपी के कारण • गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ	147
17	राजस्व व्यय और सब्सिडी	193
18	पूंजीगत व्यय	196
19	विनिवेश और निजीकरण	204
20	वित्तीय बाज़ार (Financial Markets) • परिचय • वित्तीय बाज़ार के प्रकार • शेयर बाज़ार	207
21	स्वॅप (SWAPS)	221
22	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)	222
23	वित्तीय समावेशन	228

अध्याय – 2

आर्थिक वृद्धि

आर्थिक वृद्धि को मापना

आर्थिक वृद्धि का मतलब है अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बदलाव (वृद्धि या कमी)। इसे मापना जरूरी है क्योंकि सरकार और निजी क्षेत्र के निर्णयों और नीतियों के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है। एक अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण पहलू वृद्धि से जुड़े होते हैं: कर संग्रह, ब्याज दरें, महंगाई और उसकी अपेक्षाएँ, रोजगार, विदेश व्यापार आदि। अगर वृद्धि को मापा न जाए तो कोई भी निर्णय सही तरीके से नहीं लिया जा सकता। उदाहरण के लिए, निवेश के निर्णय वृद्धि और महंगाई दर पर निर्भर करते हैं। यही कारण है कि भारत के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा बजट के प्रस्तुत होने से पहले ही वृद्धि के आंकड़े अनुमानित किए जाते हैं, ताकि राजस्व और खर्च के अनुमान को सही तरीके से पेश किया जा सके, जिससे निजी क्षेत्र के निर्णय प्रभावित होते हैं।

आर्थिक वृद्धि: इसके लाभ और दुष्प्रभाव

आर्थिक वृद्धि का पहला लाभ है धन का सृजन। यह नौकरियां बनाने में मदद करती है और आय को बढ़ाती है। इसके साथ ही जीवन स्तर में वृद्धि होती है। सरकार को अधिक कर राजस्व प्राप्त होता है, जिसे वह अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकती है (फिस्कल डिविडेंड)। आर्थिक वृद्धि कर राजस्व को बढ़ाती है और सरकार को अतिरिक्त धन मिलता है, जिसे वह खर्चीले कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल करती है। उदाहरण के लिए, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), प्रधानमंत्री उज्वला योजना (PMUY), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना आदि आर्थिक वृद्धि के कारण प्राप्त कर राजस्व से ही संभव हो पाते हैं। यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है: बढ़ती हुई मांग नए पूंजीगत उपकरणों में निवेश को प्रोत्साहित करती है, जो आर्थिक वृद्धि को तेज करती है और रोजगार उत्पन्न करती है।

दुष्प्रभाव

आर्थिक वृद्धि के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि असमानताएँ, पर्यावरणीय प्रदूषण, मानसिक तनाव आदि।

आर्थिक वृद्धि को मापने की आवश्यकता

आर्थिक वृद्धि के अध्ययन और मापने के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं:

- **लक्ष्यों के अनुरूप वृद्धि का मूल्यांकन:** जब वृद्धि को माप लिया जाता है, तो हम यह समझ सकते हैं कि क्या यह अर्थव्यवस्था के निर्धारित लक्ष्यों के लिए पर्याप्त है या नहीं। इससे हम इसकी क्षमता को समझ सकते हैं और उसी के अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं।
- **स्थिरता के लिए वृद्धि दरों को समायोजित करना:** वृद्धि की दरों को इस तरह से समायोजित किया जा सकता है कि यह स्थिर बनी रहे और आर्थिक स्थिरता बनी रहे।
- **महंगाई और मंदी पर नियंत्रण:** यदि हम अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को संख्यात्मक रूप से देखते हैं, तो हम महंगाई (inflation) या मंदी (deflation) को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।
- **तीन प्रमुख क्षेत्रों की योगदान का संतुलन:** हम आर्थिक विकास के दिशा को राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर मोड़ सकते हैं, जैसे हाल ही में भारत में कृषि से विनिर्माण क्षेत्र की ओर बढ़ना।
- **रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य:** हम रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के उचित स्तरों को लक्ष्य बना सकते हैं और इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विचार कर सकते हैं।
- **सरकारी उद्देश्यों के लिए कर राजस्व का पूर्वानुमान:** वृद्धि को मापने से सरकार को राजस्व की सही अनुमानित राशि का पता चलता है, जिससे उसके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है।
- **व्यावसायिक निवेश की योजना:** कंपनियां अपने व्यापारिक निवेश की योजना बना सकती हैं, ताकि वे आर्थिक वृद्धि के हिसाब से सही समय पर निवेश कर सकें।

आर्थिक वृद्धि का आत्म-नाशक प्रभाव

आर्थिक वृद्धि का एक आत्म-नाशक प्रभाव भी हो सकता है। यदि इसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाए तो इसके पर्यावरणीय लागत बहुत अधिक हो सकती है। इसके अलावा, असमानता के कारण समाज में ध्रुवीकरण (polarization) हो सकता है, जो अस्थिरता और उग्रवाद को बढ़ावा दे सकता है।

इसलिए, जब तक वृद्धि को मापा नहीं जाता, तब तक वृद्धि दरों की गणना नहीं की जा सकती। ऐसे आंकड़ों के बिना, आर्थिक निर्णय—निवेश और उपभोग दोनों—असंगत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था महान मंदी (1929-39) से तभी उबर सकी जब डेटा उपलब्ध हुआ। इसी कारण, अर्थशास्त्री **साइमन कुज़नेट्स** ने 1930 के दशक में **राष्ट्रीय आय** (National Income) की अवधारणा दी, जिससे सभी आर्थिक उत्पादन (व्यक्तियों, कंपनियों, और सरकार द्वारा किया गया) को एक ही माप में समेटा जा सके। इसे आमतौर पर **सकल घरेलू उत्पाद** (GDP) और इसके रूपांतर **सकल राष्ट्रीय उत्पाद** (GNP) के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना एक जटिल और विस्तृत प्रक्रिया है। इसके लिए जो नियम और सूत्र अपनाए जाते हैं, उन्हें **राष्ट्रीय आय लेखांकन** (National Income Accounting) कहा जाता है।

GDP का परिभाषा

GDP को उस कुल बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक निर्दिष्ट अवधि (आमतौर पर एक कैलेंडर वर्ष, वित्तीय वर्ष, या एक तिमाही) में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का होता है।

GDP और GNP

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) और **GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद)** के बीच मुख्य अंतर यह है कि:

- **GDP** उस देश में होने वाले सभी उत्पादन को मापता है, चाहे वह उत्पादन देश के नागरिकों द्वारा किया गया हो या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) द्वारा।
- **GNP** उस देश के नागरिकों द्वारा पूरी दुनिया में कहीं भी किया गया उत्पादन मापता है, चाहे वह उत्पादन देश के भीतर हो या विदेश में।

GDP एक भौगोलिक अवधारणा है, क्योंकि यह उस स्थान पर आधारित है जहां उत्पादन हुआ है। वहीं **GNP** एक नागरिक से संबंधित अवधारणा है, क्योंकि यह उस व्यक्ति या देश के नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन मापता है, चाहे वह कहीं भी हो।

GNP = GDP + विदेश से आने वाली शुद्ध कारक आय

इसका मतलब है कि GDP से हमें उस उत्पादन को घटाना होता है जो विदेशी नागरिकों ने देश में किया है, और उस पर हमें जोड़ना होता है जो देश के नागरिकों ने विदेश में किया है।

उदाहरण:

मान लीजिए, अगर एक जर्मन कंपनी का कार कारख़ाना अमेरिका में चल रहा है, तो उस कारख़ाने से होने वाले लाभ को **जर्मनी के GNP** में गिना जाएगा, लेकिन उसे **अमेरिका के GDP** में गिना जाएगा।

वैश्वीकरण और MNCs के युग में एक देश का GDP दूसरे देश के GNP के समान हो सकता है।

उदाहरण के लिए: जापान के मामले में, जहां बहुत सी जापानी कंपनियाँ विदेशों में काम करती हैं, इसलिए जापान का GNP काफी अधिक होता है। जबकि **चीन का GDP पिछले दशक तक उसके GNP के लगभग समान था,** क्योंकि चीन में कई विदेशी MNCs काम कर रहे थे और उनका उत्पादन चीन के GDP में शामिल हो रहा था। लेकिन चीन की **Belt and Road Initiative** (BRI) के प्रभाव से अब उसका GNP उसके GDP से अधिक हो सकता है।

बंद अर्थव्यवस्था में GDP आमतौर पर अधिक होता है। उदाहरण के लिए, भारत में 1991 से पहले जब तक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुली नहीं थी, GDP अधिक था।

लेकिन **अधिकांश देशों के लिए** GDP और GNP के मूल्य लगभग समान होते हैं।

आयरलैंड का उदाहरण

आयरलैंड का GNP उसके GDP से काफी अधिक होता है। यहां पर **गूगल, ऐप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर** जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों के मुख्यालय हैं, क्योंकि यहां की **कॉर्पोरेट कर (Tax) दरें बहुत कम** होती हैं। हालांकि, ये कंपनियाँ उत्पादन नहीं करतीं, सिर्फ आयरिश पंजीकरण होता है। इसलिए, यहां का GDP ऊंचा दिखता है, लेकिन यह भ्रमित करने वाला होता है क्योंकि ये कंपनियाँ असल में आयरिश नहीं हैं। आयरिश अर्थव्यवस्था के लिए ये कंपनियाँ किसी प्रकार का उत्पादन या नवाचार नहीं लातीं, जैसे चीन ने 1980 के दशक के बाद किया था।

भारत का GDP और GNP

भारत का **GDP** थोड़ा अधिक है उसके **GNP से** क्योंकि **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)** भारत में बाहर से आने वाले निवेश की तुलना में बहुत अधिक है। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियाँ विदेशों में कम उत्पादन करती हैं, जबकि विदेशी कंपनियाँ भारत में बहुत अधिक उत्पादन करती हैं।

भारत में **प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि (remittances)** 2017 में लगभग **69 बिलियन अमेरिकी डॉलर** थी, लेकिन यह बाहर जाने वाली धनराशि (जैसे ब्याज भुगतान, प्रौद्योगिकी पर रॉयल्टी आदि) से कम है।

GDP बनाम GNP

विश्लेषक अक्सर यह कहते हैं कि GDP (सकल घरेलू उत्पाद) GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) से बेहतर माप है। इसका कारण यह है कि GDP देश में होने वाली उत्पादन गतिविधियों को दर्शाता है, जहां रोजगार सृजन होता है, महंगाई पर नियंत्रण रहता है, कर (Tax) राजस्व अधिक होता है, और निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय होती है, जो विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद करता है। GNP के भी कुछ फायदे हैं, और भारत इसके अच्छे लाभार्थियों में से एक है। उदाहरण के लिए, विदेशों से रेमिटेंस (प्रेषण) प्राप्त करना, विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण करना, और विदेशों में निवेश करना ताकि विदेशी अवसरों का लाभ उठाया जा सके। लेकिन आमतौर पर यह सहमति है कि GDP अधिक महत्वपूर्ण है, जैसा कि ऊपर बताए गए कारणों से स्पष्ट है।

राष्ट्रीय आय और सकल मूल्य वर्धन (GVA)

राष्ट्रीय आय (NI) का गणना इस प्रकार की जाती है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) से अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय (NI) का मतलब है, NNP को फैक्टर कॉस्ट पर लिया जाता है।

NI = NNP - अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी

सकल मूल्य वर्धन (GVA) वह GDP है जिसमें अप्रत्यक्ष करों को घटा लिया जाता है। यह हमें GDP और कर (Tax) के संबंध को समझने में मदद करता है। अगर उत्पादन बढ़ता है और कर (Tax) वृद्धि उसी अनुपात में नहीं होती,

तो इसका मतलब हो सकता है कि GDP का वह हिस्सा जो कर (Tax) के दायरे में नहीं आता, वह बढ़ रहा है (जैसे कृषि क्षेत्र) या फिर कर (Tax) चोरी हो रही है।

संभावित GDP

वास्तविक GDP वह है जो वर्तमान में उत्पादन हो रहा है। इसे कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। सरकार अधिक उधारी लेकर उपभोक्ता खर्च बढ़ा सकती है, ब्याज दरें घटाकर उपभोक्ता खर्च और निवेश बढ़ा सकती है, लेकिन अगर व्यापक अर्थव्यवस्था इसका सही तरीके से जवाब नहीं देती है, तो इसके अपने जोखिम होते हैं। आयात को मुक्त करके भी उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन इसका व्यापार घाटा और मुद्रा मूल्य पर प्रभाव पड़ सकता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अस्थिर हो सकता है। इस प्रकार, उत्पादन वृद्धि को स्थिर और गैर-महंगी (non-inflationary) होना चाहिए।

संभावित सकल घरेलू उत्पाद (Potential GDP) वह उत्पादन स्तर है जिसे कोई अर्थव्यवस्था स्थायी रूप से और अत्यधिक मुद्रास्फीति के बिना उत्पन्न कर सकती है। यह वह वास्तविक GDP का उच्चतम स्तर है जिसे दीर्घकालिक रूप से बनाए रखा जा सकता है। स्थिरता से मतलब है कि कीमतें, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा (वस्त्रों और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि मुद्रा दर घटाकर नहीं होनी चाहिए) और वित्तीय क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) का जमावड़ा आदि संतुलित बने रहें।

संभावित उत्पादन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन और कौशल, संभावित श्रमिक बल (जो जनसांख्यिकी पर निर्भर करता है), तकनीकी विकास का स्तर और श्रमिक उत्पादकता। इन कारकों के कारण उत्पादन वृद्धि की सीमा निर्धारित होती है।

आउटपुट गैप (Output Gap)

आउटपुट गैप का मतलब है वास्तविक GDP और संभावित GDP के बीच का अंतर। जब वास्तविक GDP बढ़ता है और संभावित GDP से ऊपर रहता है, तो इसे सकारात्मक गैप कहा जाता है, और यह मुद्रास्फीति का कारण बनता है क्योंकि मांग आपूर्ति से अधिक होती है, जो अधिक पैसे के कारण हो सकता है। इस स्थिति में मांग वृद्धि वेतन वृद्धि के कारण भी हो सकती है, जो मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है। दूसरी ओर, यदि वास्तविक GDP संभावित GDP से नीचे रहता है, तो इसे नकारात्मक गैप कहते हैं, और इस स्थिति में मुद्रास्फीति कम हो जाती है। रोजगार के दृष्टिकोण से, जब गैप सकारात्मक होता है, तो पूरा रोजगार (सभी लोग जो काम ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें काम मिल जाता है) और उत्पादकता भी बढ़ती है।

आदर्श रूप से, संभावित GDP को पार नहीं करना चाहिए, जैसा कि ऊपर दिए गए कारणों से समझाया गया है। इसके लिए सरकार की राजकोषीय नीति और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति का सही उपयोग किया जाता है।

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income)

प्रति व्यक्ति आय, GDP या GNP को संबंधित वर्ष की मध्य वर्ष जनसंख्या से विभाजित करके निकाली जाती है। यह प्रति व्यक्ति आय एक संकेतक के रूप में प्रयोग की जाती है, जो यह बताती है कि देश कितना अमीर या गरीब है, उसका जीवन स्तर कैसा है, आदि। लेकिन, जैसे सभी औसत होते हैं, वैसे ही प्रति व्यक्ति आय भी केवल सीमित रूप से ही देश की समृद्धि को दर्शाती है, क्योंकि अक्सर देशों में गहरी असमानताएँ होती हैं, जो इस आंकड़े को सही तरीके से नहीं दर्शातीं।

GDP का अनुमान लगाना (Estimating GDP)

GDP को मापने के तीन मुख्य तरीके हैं:

1. **उत्पादन दृष्टिकोण (Output Approach)**: इसमें अंतिम वस्त्रों और सेवाओं का बाज़ार मूल्य जोड़ा जाता है।
2. **व्यय दृष्टिकोण (Expenditure Approach)**: इसमें उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और नेट निर्यात (निर्यात से आयात घटाकर) को जोड़ा जाता है।
3. **आय दृष्टिकोण (Income Approach)**: इसमें उन सभी कारकों की आय को जोड़ा जाता है जो उत्पादन में लगे होते हैं जैसे कि वेतन, मुनाफ़ा, किराया आदि।

इन तीनों तरीकों से प्राप्त परिणाम समान होने चाहिए क्योंकि वस्त्रों और सेवाओं पर कुल खर्च (GNE) का मूल्य उत्पादित वस्त्रों और सेवाओं (GNP) से समान होना चाहिए, जो अंततः उन कारकों के द्वारा निर्मित आय के बराबर होता है। लेकिन वास्तविकता में, विभिन्न तरीकों से प्राप्त परिणामों में मामूली अंतर हो सकता है, क्योंकि माल की सूची (inventory) में परिवर्तन हो सकता है। इसका कारण यह है कि माल जो स्टॉक में है, वह उत्पादन में शामिल होता है, लेकिन अभी तक बेचा नहीं गया है। इसके अलावा, भुगतान भी नहीं हुआ हो सकता है, जैसे कि कर्ज़ पर ब्याज, वेतन या किराया, जो अभी नहीं चुकाए गए हैं। इसलिए, माल और सेवाओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है, लेकिन यह आय या खर्च के साथ मेल नहीं खाता है। सूची (inventory) उन सभी वस्त्रों का विस्तृत विवरण है जो स्टॉक में हैं।

GDP में केवल विपणन (marketed) वस्त्रों को ही शामिल किया जाता है। अगर एक सफाईकर्मी को काम पर रखा जाता है, तो उसका भुगतान GDP में शामिल होता है, लेकिन अगर कोई खुद काम करता है, तो वह GDP में नहीं आता। इस प्रकार, घरों में महिलाओं द्वारा किए गए कई कार्य जैसे बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, घरेलू कार्य आदि, जो 'केयर इकोनॉमी' के अंतर्गत आते हैं, GDP में शामिल नहीं होते। इसी प्रकार, अगर बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ाता है, तो वह भी राष्ट्रीय खाता (National Accounts) में शामिल नहीं होता।

GDP की गणना में केवल अंतिम वस्त्रों और सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसका मतलब है कि जो वस्त्र

यह सूत्र बताता है कि **बाजार मूल्य (MP)** कैसे **कारक लागत (FC)** से जुड़ा होता है। इसमें अप्रत्यक्ष करों (जैसे GST, कस्टम ड्यूटी आदि) को घटाने और सब्सिडी को जोड़ने से यह प्राप्त होता है।

GDP को **कारक लागत** पर मापने का तरीका यह देखने में मदद करता है कि **बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बलों की स्थिति** कैसी है और अप्रत्यक्ष करों का क्या प्रभाव है। अगर उत्पादन के कारकों की उत्पादकता उच्च है, तो सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं होती।

दोनों मूल्यों के बीच का अंतर यह दिखाता है कि अप्रत्यक्ष करों के कारण GDP पर कितनी प्रभावी धारणा (impact) पड़ती है। यह विभेदन (differentiation) सरकारी नीतियों को बेहतर बनाने में मदद करता है ताकि अप्रत्यक्ष करों और सब्सिडी को बेहतर तरीके से समझा जा सके और उन्हें तर्कसंगत (rationalize) किया जा सके। अगर सरकार उच्च अप्रत्यक्ष करों और साथ ही काफी अधिक सब्सिडी लागू कर रही है, तो इन दोनों को समान रूप से घटाया जा सकता है ताकि लेखांकन प्रक्रिया सरल हो जाए।

हस्तांतरण भुगतान (Transfer Payments)

कुछ सरकारी खर्च ऐसे होते हैं जो वस्त्रों और सेवाओं की प्राप्ति से संबंधित होते हैं और जो सीधे उत्पादन प्रक्रिया में जाते हैं। ये GDP का हिस्सा होते हैं।

वहीं कुछ खर्च जैसे पेंशन, छात्रवृत्तियाँ (scholarships), और सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI), वे पैसे के सीधे हस्तांतरण होते हैं और ये सीधे संसाधनों को अवशोषित नहीं करते और न ही उत्पादन उत्पन्न करते हैं। इन्हें **हस्तांतरण भुगतान** कहा जाता है। ये एक प्रकार के "एकतरफा" भुगतान होते हैं, जिनमें कोई वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं होती है।

सरकार इन हस्तांतरण भुगतानों का उपयोग **आय पुनर्वितरण** के एक साधन के रूप में करती है, जैसे कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में - जैसे **सामाजिक सुरक्षा**, **वृद्धावस्था पेंशन**, **विकलांगता पेंशन**, **छात्रवृत्तियाँ**, **बेरोजगारी भत्ता**, आदि।

इनको **सब्सिडी** से अलग करना ज़रूरी है। **सब्सिडी** (जैसे निर्यातकों, किसानों, या उत्पादकों को दी जाती है) को **हस्तांतरण भुगतान** नहीं माना जाता, क्योंकि ये आर्थिक लेन-देन से जुड़े होते हैं।

हस्तांतरण भुगतान **व्यक्तिगत आय** का हिस्सा होते हैं। उदाहरण:

- **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY)**: इसमें गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में संस्थागत प्रसव कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि बच्चों के टीकाकरण और पोषण के लिए भी उपयोग होती है। इस योजना का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को घटाना है। यह **कंडीशनल कैश ट्रांसफर** है, क्योंकि यह एक शर्त के तहत दी जाती है।
- **रायथू बंधु योजना (Farmers' Investment Support Scheme - FISS)**: यह तेलंगाना सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जो किसानों को रबी और खरीफ मौसम में फसल के लिए निवेश सहायता प्रदान करती है। इसमें किसानों को प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाती है। यह **डायरेक्ट कैश ट्रांसफर** है, क्योंकि पैसे सीधे किसानों के खाते में जमा किए जाते हैं।

❖ GDP और NDP (Net Domestic Product)

GDP एक **सकल मूल्य** है, जिसमें सभी वस्त्रों और सेवाओं का उत्पादन मूल्य शामिल होता है। लेकिन, उत्पादन प्रक्रिया में जो उत्पादक मशीनरी और बुनियादी ढांचा उपयोग होता है, वह समय के साथ टूट-फूट (wear and tear) का सामना करता है। इस टूट-फूट की **मूल्य ह्रास (depreciation)** को जोड़कर हम **शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP)** प्राप्त कर सकते हैं।

NDP वह GDP होता है जिसमें **मूल्य ह्रास** को घटा दिया जाता है। इसका मतलब है कि NDP केवल उसी मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो नए उत्पादन से उत्पन्न होता है, न कि पुराने या टूट-फूट वाले उपकरणों से।

NDP = GDP - Depreciation

इसलिए, **NDP** का उपयोग उस वास्तविक उत्पादन को मापने के लिए किया जाता है जो स्थिर उत्पादन क्षमता के साथ होता है, जबकि **GDP** में टूट-फूट का असर भी शामिल होता है।

वास्तविक और नाममात्र GDP (Real and Nominal GDP)

नाममात्र GDP (Nominal GDP) वह GDP है, जिसमें महंगाई (inflation) को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसका मतलब है कि यह GDP केवल वर्तमान मूल्य पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि पिछले साल का उत्पादन समान है, लेकिन महंगाई के कारण इस साल का बाज़ार मूल्य बढ़ जाता है, तो नाममात्र GDP में भी वृद्धि होगी, भले ही वास्तविक उत्पादन वही रहे।

वास्तविक GDP (Real GDP) वह GDP होता है जिसमें उत्पादन की वर्तमान वर्ष की वस्त्रों और सेवाओं का मूल्य **तुलना वर्ष (Base Year)** के कीमतों पर मूल्यांकन किया जाता है। इसे **बेस वर्ष** की कीमतों पर मूल्यांकित किया जाता है ताकि महंगाई (या मंहगाई की कमी) के प्रभाव को हटा दिया जाए।

इसका उद्देश्य **वास्तविक उत्पादन** को मापना है, क्योंकि केवल नाममात्र GDP में महंगाई के कारण उत्पन्न मूल्य वृद्धि को देखा जाता है, जो वास्तविक उत्पादन के बारे में गलत धारणा बना सकता है। वास्तविक GDP यह दर्शाता है कि एक देश ने वस्त्रों और सेवाओं का वास्तविक उत्पादन कितना किया है, बिना मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को शामिल किए।

उदाहरण:

- मान लीजिए पिछले साल 10 सेब का उत्पादन हुआ और उनका कुल बाज़ार मूल्य 10 रुपये था।
- अगर इस साल वही 10 सेब का उत्पादन हुआ, लेकिन इस साल महंगाई के कारण इनका बाज़ार मूल्य 15 रुपये हो गया, तो नाममात्र GDP 15 रुपये हो जाएगा।
- लेकिन वास्तविक GDP वही रहेगा जो पिछले साल था, यानी 10 रुपये, क्योंकि यह पिछले साल की कीमतों पर आधारित है।

GDP Deflator

GDP डिफ्लेटर (GDP Deflator) वह साधन है, जिसका उपयोग वास्तविक GDP की गणना में किया जाता है। यह **महंगाई के प्रभाव को निकालने** के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि हम वास्तविक उत्पादन का सही आंकड़ा प्राप्त कर सकें।

यह एक प्रकार का **मूल्य सूचकांक (Price Index)** है, जो यह दिखाता है कि महंगाई के कारण वर्तमान उत्पादन का मूल्य पिछले वर्ष (या बेस वर्ष) के मुकाबले कितना बढ़ा है। जब हम वर्तमान उत्पादन को पिछले वर्ष की कीमतों पर मूल्यांकित करते हैं, तो यह मूल्य परिवर्तन (महंगाई या संकुचन) को पकड़ता है।

उदाहरण:

- मान लीजिए कि पिछले साल (बेस वर्ष) 10 सेब का उत्पादन हुआ और उनका मूल्य 10 रुपये था, तो GDP का मूल्य 10 रुपये होगा।
- इस साल, अगर वही 10 सेब का उत्पादन हुआ, लेकिन इनका मूल्य 15 रुपये हो गया, तो नाममात्र GDP 15 रुपये हो जाएगा।
- लेकिन, **GDP डिफ्लेटर** यह दिखाएगा कि महंगाई कितनी थी। अगर 10 सेब का उत्पादन इस साल भी 10 रुपये का होता और अब वे 15 रुपये में बिकते, तो इसका मतलब है कि महंगाई 50% थी।

GDP डिफ्लेटर की गणना इस प्रकार की जाती है:

$$\text{GDP Deflator} = \left(\frac{\text{Nominal GDP}}{\text{Real GDP}}\right) \times 100$$

- **Nominal GDP** वह GDP है जो वर्तमान कीमतों पर मापा गया होता है।
- **Real GDP** वह GDP है जो बेस वर्ष की कीमतों पर मापा गया होता है।

यदि GDP डिफ्लेटर की **मान** बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि महंगाई (inflation) हो रही है, और यदि यह घटती है, तो इसका मतलब है कि **संकुचन (deflation)** हो रहा है।

GDP Deflator और महंगाई (Inflation)

GDP डिफ्लेटर महंगाई का एक माप है, जो पूरी अर्थव्यवस्था में मूल्य परिवर्तन (price changes) को ट्रैक करता है। यह **वितरण मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index - WPI)** और **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index - CPI)** के विपरीत, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है, न कि केवल कुछ विशेष वस्त्रों और सेवाओं के समूह का।

GDP Deflator निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है:

- यह केवल उन वस्त्रों और सेवाओं के मूल्य परिवर्तन को मापता है, जो GDP का हिस्सा हैं।
- यह एक **समय आधार** पर मापने वाला सूचकांक है, जिसे गणना के लिए **राष्ट्रीय खाता डेटा** से लिया जाता है।
- यह एक **दीर्घकालिक** सूचकांक होता है और इसमें **विलंब** होता है, इसलिए इसे शॉर्ट-टर्म मूल्य स्थिरता (price stability) मापने के लिए कम उपयोग किया जाता है।

GDP और Deflation (संकुचन)

यदि **GDP डिफ्लेटर नकारात्मक (negative)** होता है, तो इसका मतलब है कि **नाममात्र GDP** वास्तविक GDP से कम है, जो **संकुचन (deflation)** की स्थिति को दर्शाता है। इस स्थिति में, **मूल्य स्तर (price level)** में गिरावट आ रही है, और अर्थव्यवस्था में संकुचन हो रहा है।

उदाहरण:

अगर नाममात्र GDP 10 रुपये है, और वास्तविक GDP 15 रुपये है, तो GDP डिफ्लेटर का मान (-33.33%) होगा, जो दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में **मूल्य संकुचन (deflation)** हो रहा है।

इस प्रकार, **GDP डिफ्लेटर** का उपयोग अर्थव्यवस्था में **मूल्य परिवर्तनों (price changes)** को समझने और वास्तविक उत्पादन को मापने के लिए किया जाता है, ताकि महंगाई या संकुचन का सही आकलन किया जा सके।

आधार वर्ष (Base Year)

आर्थिक विकास को मापने के लिए किसी प्रारंभिक समय बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे **आधार वर्ष** (Base Year) कहा जाता है। यह वर्ष उस समय की पूरी उत्पादन को दर्शाता है, जो GDP में शामिल होता है, और इसी के आधार पर अगले वर्षों के विकास का माप प्रतिशत में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आधार वर्ष 2011-12 में GDP 100 रुपये है और अगले वर्ष (2012-13) में यह 108 रुपये हो जाता है, तो विकास दर 8% होगी। इस उदाहरण में, दोनों वर्षों में समान वस्तुएं और सेवाएं मापी जाती हैं। अगर आधार वर्ष के बाद नए उत्पादों का निर्माण होता है,

अध्याय – 8

धन और बैंकिंग

धन या ऋण निर्माण प्रक्रिया

अर्थव्यवस्था में धन की भूमिका को समझने के लिए धन निर्माण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसकी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि बैंक अपने ग्राहकों की निकासी को पूरा करने के लिए कितना धन आरक्षित रखते हैं। यह अभ्यास ग्राहकों को यह मानते हुए दूसरों को धन उधार देने का है कि सभी ग्राहक एक ही समय में अपना सारा धन वापस नहीं लेना चाहेंगे, इसे अंशधार आरक्षित बैंकिंग कहते हैं।

हम एक सरल उदाहरण के माध्यम से यह कैसे काम करता है, इसका वर्णन कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था में बैंकरों का विचार है कि उन्हें उनके पास जमा किए गए किसी भी धन का केवल 10 प्रतिशत ही रखना होगा। इसे आरक्षित आवश्यकता के रूप में जाना जाता है। अब विचार करें कि क्या होता है जब कोई ग्राहक बैंक X में ₹100 जमा करता है। यह जमा बैंक X की बैलेंस शीट को बदल देता है और यह बैंक के लिए देयता का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यह ग्राहक द्वारा बैंक को प्रभावी रूप से उधार दिया जाता है। इस जमा का 90 प्रतिशत किसी अन्य ग्राहक को उधार देकर बैंक के पास दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं: (1) बैंक का ₹10 के आरक्षित, और (2) ₹90 के बराबर ऋण।

अब मान लीजिए कि ₹90 के ऋण प्राप्तकर्ता इस पैसे का उपयोग इस मूल्य के कुछ सामान खरीदने के लिए करता है और माल का विक्रेता इस ₹90 को किसी अन्य बैंक, बैंक Y में जमा करता है। बैंक Y उसी प्रक्रिया से गुजरता है; यह ₹9 का आरक्षित रखता है और जमा राशि (₹81) का 90 प्रतिशत किसी अन्य ग्राहक को उधार देता है। यह ग्राहक बदले में कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर ₹81 खर्च करता है। इस धन का प्राप्तकर्ता इसे बैंक Z में जमा करता है, और इसी तरह आगे बढ़ता है।

यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि जमा करने और उधार देने के लिए कोई और पैसा न बचे। ₹100 के इस एक जमा से बनाई गई कुल राशि की गणना इस प्रकार की जा सकती है:

नई जमा/आरक्षित आवश्यकता = ₹100/0.10 = ₹1,000

परिभाषाएँ:

पैसा सृजन की प्रक्रिया एक मूलभूत प्रश्न उठाती है: पैसा क्या है? एक ऐसे अर्थव्यवस्था में, जहाँ पैसा होता है लेकिन प्रॉमिसरी नोट्स और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग नहीं होती, पैसा अपेक्षाकृत आसान होता है परिभाषित करने के लिए: पैसा वह कुल राशि है जो संचार में सोने और चांदी के सिक्कों में होती है, या उनका समान रूप। हालांकि, ऊपर दी गई पैसा सृजन की प्रक्रिया यह संकेत देती है कि पैसे की एक व्यापक परिभाषा में संचार में मौजूद सभी नोट और सिक्के और सभी बैंक जमा शामिल हो सकते हैं। सामान्य रूप से, हम पैसे को किसी भी ऐसे माध्यम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसे माल और सेवाओं को खरीदने के लिए उपयोग किया जा सके। नोट और सिक्कों का उपयोग इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, और फिर भी ऐसी मुद्रा माल और सेवाओं को खरीदने का एकमात्र तरीका नहीं है। व्यक्तिगत चेक एक बैंक चेकिंग खाते पर आधारित लिखे जा सकते हैं, जबकि डेबिट कार्ड भी उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। लेकिन समय जमा या बचत खातों के बारे में क्या? आजकल, बचत खाते से चालू खाते में धन का स्थानांतरण अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है; इसलिए, इन बचत खातों को भी पैसे के भंडार का हिस्सा माना जा सकता है। क्रेडिट कार्ड भी माल और सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं; हालांकि, क्रेडिट कार्ड भुगतान और चेक या डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। चेक या डेबिट कार्ड के भुगतान के विपरीत, क्रेडिट कार्ड भुगतान में एक विलंबित भुगतान होता है। मूल रूप से, किसी भी वित्तीय प्रणाली की जटिलता जितनी अधिक होती है, पैसा परिभाषित करना उतना ही कठिन होता है।

चूँकि वित्तीय प्रणालियाँ, प्रथाएँ और संस्थाएँ विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न होती हैं, इसलिए पैसों की परिभाषाएँ भी भिन्न होती हैं; इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय तुलना करना कठिन होता है। फिर भी, अधिकांश केंद्रीय बैंक पैसे के संकीर्ण और व्यापक मापदंड दोनों का उत्पादन करते हैं, साथ ही कुछ मध्यवर्ती मापदंड भी।

पैसा की सबसे सामान्य परिभाषा यह है कि यह कोई भी सामान्यतः स्वीकृत विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम कोई भी संपत्ति हो सकती है जिसका उपयोग माल और सेवाओं को खरीदने के लिए या कर्ज चुकाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, पैसा उस विघटनकारी "चाहतों" की समस्या को समाप्त कर सकता है जो बार्टर अर्थव्यवस्था में मौजूद होती है।

हालाँकि, धन को विनिमय के इस मुक्तिदायक माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए, इसमें कुछ गुण होने चाहिए।

यह अवश्य होना चाहिए:

- तत्परता से स्वीकार्य
- एक ज्ञात मूल्य होना चाहिए
- आसानी से विभाज्य होना चाहिए
- अपने वजन के सापेक्ष उच्च मूल्य होना चाहिए और
- नकली बनाना मुश्किल होना चाहिए।

धन और बैंकिंग एक मजबूत और प्रभावी आर्थिक और वित्तीय प्रणाली की आधारशिला है।

लेकिन धन और बैंकिंग दोनों सदियों से विकसित होकर आज जहाँ हैं वहाँ पहुँचे हैं। अतीत में बहुत लंबे समय तक, दोनों में से किसी की भी कोई अवधारणा नहीं थी।

लोग आपस में वस्तुओं का आदान-प्रदान करते थे यानी वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। वस्तु विनिमय प्रणाली ने लोगों को उन चीजों को प्राप्त करने का एक तरीका प्रदान किया जो उनके पास नहीं थीं।

और जब तक हमने अधिशेष का उत्पादन शुरू नहीं किया, तब तक हमने कुछ भी बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं की। निर्वाह पर्याप्त था। लेकिन एक बार जब उत्पादन उचित स्तर पर पहुँच गया और मौजूदा वस्तु विनिमय प्रणाली की अन्य अंतर्निहित समस्याओं के कारण लोग धीरे-धीरे एक अधिक सूक्ष्म अवधारणा - धन की ओर बढ़ गए और समय के साथ अन्य जटिल कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बैंकिंग प्रणाली का भी आविष्कार किया गया।

वास्तव में, धन और बैंकिंग के विकास का इतिहास अक्सर आपस में जुड़ा हुआ है।

भारत में भी हमें वैदिक काल के दौरान दिए जा रहे ऋणों के प्रमाण मिलते हैं। मौर्य काल में, आदेश नामक एक उपकरण उपयोग में था, जो एक बैंकर पर एक आदेश था जो उसे नोट के पैसे को किसी तीसरे व्यक्ति को देने की इच्छा रखता था, जो आज हम समझते हैं कि विनिमय के बिल की परिभाषा से मेल खाता है।

इसलिए, हम देख सकते हैं कि जबकि आधुनिक धन और बैंकिंग प्रणाली अब बहुत बड़ी और उन्नत लग सकती है, लेकिन यह सब सदियों पहले लोगों के बीच वस्तुओं के साधारण आदान-प्रदान से शुरू हुआ था।

यह सब वस्तु विनिमय प्रणाली से शुरू होता है।

वस्तु विनिमय प्रणाली: धन के माध्यम से वस्तुओं का आदान-प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है।

पहले के समय में, जब धन और बैंकिंग की कोई अवधारणा नहीं थी, लोग विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे। वे वस्तुओं का आदान-प्रदान करते थे।

आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझाते हैं:

मान लीजिए कि मैं कपड़े खरीदना चाहता हूँ और मेरे पास 1 किलो सेब हैं। अब, मुझे बस एक ऐसे व्यक्ति को खोजने की ज़रूरत है जो सेब चाहता है और बेचने के लिए कपड़े हैं। मैं उस व्यक्ति से संपर्क करूँगा और हम दोनों पारस्परिक रूप से सहमत सौदे को अंतिम रूप देंगे जिसमें मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूँ (कपड़े) और दूसरे व्यक्ति को वह मिलेगा जो वह चाहता है (सेब)। दोनों पक्ष संतुष्ट होकर घर लौटते हैं। यह लेनदेन वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत सफलतापूर्वक किया गया है।

लेकिन इस प्रणाली में कुछ स्पष्ट समस्याएँ हैं।

वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख समस्याएँ:

वस्तु विनिमय में कई मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख हैं:

- **आवश्यकताओं का दोहरा संयोग:** हर किसी को एक ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जो वह खरीदने को तैयार हो जो वे बेचने को तैयार हैं और एक ऐसा व्यक्ति जो वह बेचने को तैयार हो जो वे खरीदना चाहते हैं। उपरोक्त उदाहरण में, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की ज़रूरत है जिसके पास बेचने के लिए अतिरिक्त कपड़े हों और न केवल यह बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो कपड़ों के बदले में सेब भी चाहता हो।
- **धन को आगे बढ़ाना मुश्किल:** उपरोक्त उदाहरण में, मैं अनिश्चित काल के लिए सेबों का भंडारण नहीं कर सकता। वे सोने या नकदी की तरह धन के भंडार के रूप में कार्य नहीं कर सकते।
- **खाते की एक मानक इकाई का अभाव:** मुझे कितने कपड़ों के बदले में कितने सेब देने चाहिए, यह उपरोक्त उदाहरण में हमेशा एक मुद्दा होगा। खाते की कोई मानक इकाई नहीं है।

जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं, एक लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए, शामिल पक्षों के लिए स्वीकार्य विनिमय के एक सामान्य माध्यम की आवश्यकता थी। इसलिए, धन की अवधारणा उत्पन्न हुई।

अब, एक व्यक्ति पैसे के लिए सेब बेचने और कमाए गए पैसे से कपड़े खरीदने में सक्षम था। इसी तरह, दूसरा व्यक्ति पैसे के लिए कपड़े बेचने और फिर उस पैसे से सेब खरीदने में सक्षम था।

ध्यान दें: वस्तु विनिमय प्रणाली के अपने फायदे भी हैं, जैसे कि मौद्रिक संकट या अति मुद्रास्फीति के मामलों में जब मुद्रा अपना मूल्य खो देती है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक विकल्प के रूप में पूरी तरह से काम करती है।

UPSC की तैयारी के लिए धन और बैंकिंग एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इसे पूरी तरह से समझने के लिए व्यक्ति को धन, मुद्रा आपूर्ति, मौद्रिक समुच्चय आदि जैसी अंतर्निहित अवधारणाओं से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए।

धन क्या है?

धन विनिमय का सबसे आम तौर पर स्वीकृत माध्यम है।

- कोई भी वस्तु जो आम तौर पर भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार की जाती है। नोट या सिक्कों के रूप में मुद्रा, एक प्रकार का धन है।
- याद रखें कि धन कोई आवश्यकता नहीं है और हमारा समाज इसके बिना भी मौजूद रह सकता है। यह केवल एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है।

धन के कार्य:

1. **यह विनिमय** के माध्यम के रूप में कार्य करता है: किसी भी वस्तु को पैसे से खरीदा जा सकता है।
2. **मूल्य का एक सामान्य माप:** सभी वस्तुओं का अपना मूल्य होता है जो पैसे के रूप में व्यक्त किया जाता है।
3. मूल्य का भंडार
4. स्थगित भुगतानों के लिए एक मानक के रूप में कार्य करता है: भविष्य के मौद्रिक दायित्वों को पैसे का उपयोग करके

निपटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आज लिया गया ऋण किश्तों में चुकाया जाता है।

धन के प्रकार:

1. पूर्ण-मूल्य मुद्रा
2. सांकेतिक मुद्रा (कागज मुद्रा/साख मुद्रा)
3. कागज मुद्रा

प्रतिनिधि पूर्ण-मूल्य कागज मुद्रा, अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा

- फ़िएट मुद्रा
- वैध मुद्रा
- गैर-वैध मुद्रा/वैकल्पिक मुद्रा
- फ़िड्यूशियरी मुद्रा
- निकट मुद्रा
- प्लास्टिक मुद्रा
- जमा मुद्रा

पूर्ण-मूल्य मुद्रा:

- वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। पूरा मूल्य स्वयं मुद्रा में अंतर्निहित होता है।
- मुद्रा मूल्य = वस्तु मूल्य
- उदाहरण के लिए; सोने की मुद्रा

सांकेतिक मुद्रा:

- धन के रूप में इसका मूल्य वस्तु के रूप में इसके मूल्य से कहीं अधिक है।
- मुद्रा मूल्य > वस्तु मूल्य उदाहरण के तौर पर, निम्नलिखित दो सिक्कों पर विचार करें:
- एक सिक्का सोने का है और इसका मुद्रा मूल्य 1000 रुपये है (अर्थात आप इस सिक्के से इतनी कीमत की चीजें खरीद सकते हैं)।
- दूसरा सिक्का तांबे का है और इसका मुद्रा मूल्य 10 रुपये है।
- अब, सोने के सिक्के से कुछ खरीदने के बजाय, यदि आप इसे बाजार में एक वस्तु के रूप में बेचने का निर्णय लेते हैं, तो आपको अभी भी 1000 रुपये मिलेंगे क्योंकि सिक्के के अंदर उतना ही सोना है यानी इसका आंतरिक मूल्य 1000 रुपये है। इस प्रकार की मुद्रा को पूर्ण-मूल्य मुद्रा कहा जाता है।
- दूसरी ओर, यदि आप तांबे के सिक्के को बाजार में एक वस्तु के रूप में बेचने का निर्णय लेते हैं तो आपको 10 रुपये भी नहीं मिलेंगे क्योंकि इस तांबे के सिक्के को सौंपा गया मुद्रा मूल्य तांबे के संदर्भ में इसके वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक है।
- इस प्रकार की मुद्रा को सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है।
- इस प्रकार की मुद्रा का एक और उदाहरण एक कागजी नोट है। यदि आप इसे बाजार में एक वस्तु के रूप में बेचने का निर्णय लेते हैं तो 500 रुपये का नोट बहुत कम मूल्य का होता है (एक वस्तु के रूप में यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिस पर 500 रुपये लिखा होता है। उस कागज का कोई मूल्य नहीं होगा)।

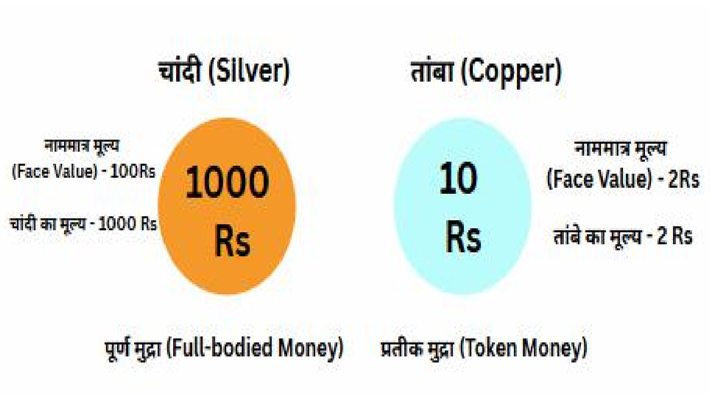

कागज मुद्रा

कागज से बने पैसे को कागज मुद्रा कहा जाता है। इसे आगे दो भागों में विभाजित किया गया है:

प्रतिनिधि पूर्ण-मूल्य कागज मुद्रा/परिवर्तनीय मुद्रा:

- यह एक प्रकार की कागज मुद्रा है जो जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा सोने/चांदी (बुलियन) की समतुल्य राशि के बदले में जारी की जाती है।
- इस प्रकार की कागज मुद्रा रखने वाला कोई भी व्यक्ति केंद्रीय बैंक जा सकता है और उसे सोने या चांदी की समतुल्य राशि में परिवर्तित कर सकता है यानी इस प्रकार की कागज मुद्रा को पूर्ण-मूल्य मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए इसे परिवर्तनीय मुद्रा भी कहा जाता है।
- **अपरिवर्तनीय मुद्रा:** इस प्रकार की कागज मुद्रा को सोने या चांदी की समतुल्य राशि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
- केंद्रीय बैंक पर इसे परिवर्तित करने का कोई दायित्व नहीं है।
- भारत में वर्तमान में सांकेतिक मुद्रा है। RBI पर प्रतिनिधि कागज मुद्रा को सोने/चांदी की समतुल्य राशि में परिवर्तित करने का ऐसा कोई दायित्व नहीं है।
- ध्यान दें: सांकेतिक मुद्रा पूरी तरह से सरकार में लोगों के विश्वास पर आधारित है।
- मध्यकालीन भारत के एक समय पर विचार करें।
- आप एक ऐसे राज्य में रहते हैं जिसकी अपनी पूर्ण-मूल्य सिक्का प्रणाली है। सिक्के सोने के बने होते हैं।
- एक वर्ष बाद एक नया शासक आता है जो कहता है कि वह पिछले सभी सिक्कों को समाप्त कर रहा है और अपने नाम पर नए सिक्के जारी कर रहा है।
- यह एक अचानक अखिल-आर्थिक विमुद्रीकरण के समान है जहाँ हर सिक्के को विमुद्रीकृत कर दिया जाता है।
- आपकी संपत्ति का क्या होगा? आपके पास पिछली शासन व्यवस्था के 1000 सिक्के हो सकते हैं लेकिन अब वे बेकार

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

जमा मुद्रा:
बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा किया गया पैसा। उदाहरण के लिए, आपके बचत खाते, सावधि जमा, आवर्ती जमा आदि सभी विभिन्न प्रकार की जमा मुद्रा हैं।

मजेदार तथ्य:
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे बड़ा मूल्यवर्ग का नोट 1938 में ₹10000 का नोट था जिसे जनवरी 1946 में विमुद्रीकृत कर दिया गया था। ₹10000 को 1954 में फिर से शुरू किया गया था। इन नोटों को 1978 में विमुद्रीकृत कर दिया गया था।

मुद्रा आपूर्ति क्या है?
यह किसी भी समय जनता के पास मौजूद सभी प्रकार के धन का कुल भंडार है।

- यहाँ 'जनता' का अर्थ सरकार और बैंकिंग प्रणाली को छोड़कर सभी आर्थिक संस्थाएँ हैं क्योंकि ये संस्थाएँ धन बनाती हैं।
- इसलिए, मुद्रा आपूर्ति (MS) है,
  MS = मुद्रा + बैंक जमा

MS किसी अर्थव्यवस्था की कुल क्रय शक्ति को दर्शाता है। मुद्रा आपूर्ति को मापने के विभिन्न तरीके हैं। इन्हें मौद्रिक समुच्चय कहा जाता है। केवल तभी जब पूरी मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति ज्ञात हो जाती है, केंद्रीय बैंक इसे विनियमित करने के लिए कदम उठा सकता है।
मौद्रिक समुच्चयों को समझाने से पहले, हमें शामिल बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

बैंक द्वारा रखी गई जमाओं के प्रकार:

- मांग जमा (DD)
- सावधि जमा (TD)
- अन्य जमा (OD)

मांग जमा: यह पैसा बैंक से कभी भी (मांग पर) निकाला जा सकता है। इन जमाओं में शामिल हैं:

- चालू खाता
- बचत खाते का मांग देयता भाग

ये जमा 100% तरल होते हैं।

सावधि जमा:
परिपक्वता के बाद या परिपक्वता से पहले जुर्माना के साथ ही पैसा निकाला जा सकता है। इनमें शामिल हैं:

- सावधि जमा
- आवर्ती जमा
- बचत खाते की समय देयता

अन्य जमा:
RBI के पास मांग जमा जिसमें सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की मांग जमा, विदेशी केंद्रीय बैंकों की मांग जमा और IMF, विश्व बैंक आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान शामिल हैं।
इसलिए,
निवल बैंक जमा = DD + TD
ध्यान दें: कुल बैंक जमा निवल बैंक जमा से भिन्न है। क्यों? क्योंकि बैंकों के पास RBI से उधार जैसी अन्य जमाएँ भी होती हैं।
अब, आइए मौद्रिक समुच्चयों पर एक नज़र डालते हैं:

मौद्रिक समुच्चय:

1. M1 (संकीर्ण मुद्रा)
2. M2 (संकीर्ण मुद्रा)
3. M3 (व्यापक मुद्रा)
4. M4 (व्यापक मुद्रा)
5. M0 (आरक्षित/उच्च-शक्ति मुद्रा)

M1 (संकीर्ण मुद्रा):

- M1 = C + DD + OD
- C – जनता के पास मौजूद मुद्रा
- DD – बैंकों के पास निवल मांग जमा (इसमें अंतरबैंक जमा शामिल नहीं है यानी वाणिज्यिक बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों में जो जमा रखते हैं)
- OD – इनमें RBI के पास कुछ व्यक्तियों (पूर्व RBI गवर्नर RBI में खाता खोल सकते हैं) और संस्थानों (IMF आदि) द्वारा रखी गई जमाएँ शामिल हैं।
- ध्यान दें - सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, OD लगभग नगण्य है।
- चूंकि M1 में शामिल पैसा सबसे तरल होता है, इसलिए इसे संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है।

M2 (संकीर्ण मुद्रा):

- M2 = M1 + डाकघर बैंकों में बचत खाता जमा
- M2 लगभग M1 के बराबर है क्योंकि डाकघर बैंकों में जमाएँ अधिक नहीं हैं।

M3 (व्यापक मुद्रा):

- M3 = M1 + TD (वाणिज्यिक बैंकों के साथ सावधि जमा जैसे सावधि जमा, आवर्ती जमा)
- M3 मुद्रा और कुल बैंक जमा को दर्शाता है। इसलिए, यह किसी अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति को दर्शाता है। M2 और M4 के मामले में डाकघर बैंकों के साथ जमा भी शामिल हैं। ये बैंक ऋण नहीं दे सकते हैं और क्रय शक्ति जनता के पास मौजूद मुद्रा और बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के बराबर है। इसलिए, M2 या M4 के बजाय, हम क्रय शक्ति दिखाने के लिए M3 का उपयोग करते हैं।
- M3 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। इसे कुल मौद्रिक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है।

M4 (व्यापक मुद्रा):

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

M4 = M3 + डाकघर बैंकों के साथ कुल जमा (राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र के तहत जमा को छोड़कर)
ध्यान दें: व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, डाकघर बैंकों के साथ कुल जमा बहुत कम है इसलिए M4 लगभग M3 के बराबर है।

बढ़ती तरलता के संदर्भ में मौद्रिक समुच्चयों को रैंक करें:

- M1
- M2
- M3
- M4

M0 (उच्च-शक्ति मुद्रा/प्राथमिक मुद्रा):

- M0 या H
- यह सरकार को छोड़कर किसी भी समय सभी प्रकार की आर्थिक संस्थाओं (जनता और बैंकों) द्वारा धारित सभी प्रकार की मुद्रा (नोट, सिक्के) का कुल भंडार है।
- M0 = C + R + OD
- C – प्रचलन में मुद्रा: यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा (सिक्के और कागजी मुद्रा) का कुल मूल्य है, जिसमें से उसके द्वारा वापस ली गई राशि घटा दी जाती है।
- R – बैंकों का नकद आरक्षित
- OD – अन्य जमा
- **ध्यान दें** - वॉल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।
- साथ ही, M3 > M0 (क्योंकि M3 में बैंकों द्वारा रखी गई जमाएँ शामिल हैं जबकि M0 में बैंकों का नकद आरक्षित और बैंकों द्वारा रखी गई जमाएँ शामिल हैं और बैंक द्वारा रखी गई जमाएँ हमेशा उसके नकद आरक्षित से अधिक होती हैं)।

मुद्रा गुणक (m):

- यह मुद्रा आपूर्ति (MS) का आरक्षित मुद्रा (M0) से अनुपात है।
- m = MS/M0

भारत में मौद्रिक प्रणाली:

- भारत 'न्यूनतम आरक्षित प्रणाली (MRS)' का पालन करता है। यह प्रणाली आनुपातिक आरक्षित प्रणाली के स्थान पर अपनाई गई थी।
- MRS के तहत, RBI को सोने और विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में कम से कम 200 करोड़ का आरक्षित रखना होता है।
- इनमें से, कम से कम 115 करोड़ सोने के रूप में बनाए रखने चाहिए।
- इन आरक्षितों के रखरखाव पर, RBI सोने, विदेशी प्रतिभूतियों और भारत सरकार की प्रतिभूतियों के समर्थन के बदले असीमित मुद्रा छाप सकता है।

वे चीजें जिनके बदले RBI पैसा छाप सकता है:

- सोना
- विदेशी प्रतिभूतियाँ
- भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (G-sec)

एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा ऋण सृजन:

अब तक, हमने धन और बैंकिंग की कुछ बुनियादी अवधारणाओं को समझा है। अब, आइए सबसे सरल शब्दों में ऋण सृजन की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले, आइए देखते हैं कि बैंक के लिए संपत्ति क्या है और देयता क्या है।

- **संपत्तियाँ:** किसी को दिए गए ऋण और अग्रिम बैंक के लिए संपत्ति हैं क्योंकि वे ब्याज उत्पन्न करते हैं। संपत्ति वह है जो भविष्य में नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है।
- **देयताएँ:** बैंक में जमा की गई जमाएँ बैंक के लिए देयताएँ हैं क्योंकि उन्हें ग्राहक को वापस भुगतान करना होता है।
- ध्यान दें: बैंकों को अंशधार आरक्षित बैंकिंग में शामिल होने की अनुमति है जिसका अर्थ है कि बैंक में जमा की गई जमाओं का एक अंश आरक्षित के रूप में रखा जाना चाहिए और शेष को ऋण के रूप में दिया जा सकता है। यह आम जनता को समस्याओं से बचाने के लिए किया जाता है।
- यह आरक्षित आवश्यकता नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के तहत की जाती है।
- SRR और CRR को एक साथ कानूनी आरक्षित अनुपात (LRR) के रूप में जाना जाता है।

ऋण सृजन की प्रक्रिया:

आपके धन और बैंकिंग की बुनियादी बातों के स्पष्ट होने के साथ, आइए देखें कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वास्तव में ऋण सृजन कैसे किया जाता है।
यहाँ हम मान लेंगे कि LRR आवश्यकता 10% है।

- मान लीजिए कि एक व्यक्ति A है जिसके पास 100 रुपये हैं। उसने इसे अभी तक बैंक में जमा नहीं किया है।
- यह सोचते हुए कि वह उस पैसे को खर्च नहीं करने वाला है और उसके पड़ोसी उसे चुराने की कोशिश कर सकते हैं, वह उस पैसे को एक बैंक में जमा करने का फैसला करता है।

- वह SBI की एक शाखा में जाता है और बचत खाते में 100 रुपये जमा करता है। यह जानकर कि उसका पैसा सुरक्षित है वह खुशी-खुशी घर वापस आ जाता है।
- **चरण 1:** इस बिंदु पर, SBI के पास ₹100 की मांग जमा है। यह इस समय एक देयता है।
- यह LRR आवश्यकता के अनुसार ₹10 का आरक्षित भी रखता है।
- इसलिए, इस बिंदु पर ऋण योग्य राशि ₹90 है, ₹100 नहीं।
- एक दिन, श्री B बैंक में प्रवेश करते हैं और ऋण मांगते हैं।
- SBI उन्हें पैसे उधार देने में बहुत खुश है। यह उन्हें ₹90 का ऋण देता है लेकिन यह ऋण स्पष्ट कारणों से नकद में नहीं दिया जाता है।
- श्री B का ICICI में एक खाता है। SBI इस राशि को उनके ICICI खाते में स्थानांतरित करता है।
- **चरण 2:** अब, ICICI को ₹90 जमा के रूप में प्राप्त होते हैं।
- यह 10% यानी ₹9 को आरक्षित के रूप में रखता है और अब यह किसी अन्य ग्राहक को ₹81 और उधार दे सकता है।
- **चरण 3:** इसी तरह, ICICI इस राशि को श्री C को उधार देगा। वह Axis बैंक में ₹81 जमा करता है।
- अब, Axis बैंक 10% (₹8.1) रखता है और अब ₹72.9 को ऋण के रूप में दे सकता है।

क्या आपने ध्यान दिया कि SBI के साथ एक प्रारंभिक जमा ने अर्थव्यवस्था में ऋण कैसे बनाया! इस तरह ऋण बनाया जाता है और इस प्रक्रिया में पैसा कई गुना बढ़ जाता है। ऋण सृजन की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि ₹100 की प्रारंभिक जमा राशि समाप्त नहीं हो जाती।

इसकी गणना करने का एक सूत्र है।

मुद्रा गुणक = 1/LRR (इस उदाहरण के लिए: मुद्रा गुणक = 1/0.1 = 10)

ऋण सृजन = प्रारंभिक जमा * मुद्रा गुणक = 100 * 10 = ₹1000

इसलिए, उपरोक्त उदाहरण में, प्रारंभिक जमा ₹100 थी जिसका अर्थ है कि ऋण सृजन 100 * 1/10% = ₹1000 के बराबर होगा।

इसलिए, इस मामले में, ₹100 अर्थव्यवस्था में ₹1000 का ऋण प्रवाह उत्पन्न करेगा।

PS: ऋण सृजन के सूत्र को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपकी बेहतर समझ के लिए दिया गया है।

ध्यान दें: कृपया याद रखें कि यहाँ हमने माना है कि सभी लोग एक ही दिन अपनी जमा राशि मांगने नहीं आएंगे। इसे बैंक रन कहा जाता है और यह शायद ही कभी होता है लेकिन अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि एक बैंक किसी को भी ऋण नहीं दे पाएगा।

हमें उम्मीद है कि अब आप धन और बैंकिंग की बुनियादी बातों से स्पष्ट हैं और इस बात का बेहतर अंदाजा है कि पूरी प्रणाली लेनदेन को प्रोत्साहित करके और अर्थव्यवस्था में बढ़े हुए ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करके समाज को लाभान्वित करने के लिए कैसे काम करती है।

यह तेजी से तकनीकी नवाचार और अनुकूलन का युग है। नतीजतन, विश्व आर्थिक और वित्तीय प्रणाली बहुत तेजी से बढ़ी है और इसके साथ ही धन की अवधारणा भी बढ़ी है। सब कुछ डिजिटाइज़ किया जा रहा है। इसने हमें एक ऐसे बिंदु पर ला दिया है जहाँ अब हमारे पास धन का एक डिजिटल रूप है यानी एक डिजिटल मुद्रा।

आइए इसके बारे में और जानें।

डिजिटल मुद्रा क्या है?

डिजिटल मुद्रा कोई भी मुद्रा है जो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है।

- क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है।
- इस दुनिया की अधिकांश मुद्राएँ डिजिटल हैं। एक अनुमान के अनुसार, दुनिया की लगभग 92% मुद्रा पहले से ही डिजिटल रूप में है। केवल 8% नकद में है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) क्या है?

बिटकॉइन, एथेरियम आदि जैसी विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्राओं की सफलता के बाद, दुनिया भर के देश अपनी खुद की डिजिटल मुद्राएँ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं जिन्हें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), या भारत में राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा के रूप में जाना जाता है।

- CBDC बस देश की फ़िएट मुद्रा का डिजिटल रूप है। कागजी मुद्रा छापने या सिक्के ढालने के बजाय, केंद्रीय बैंक इलेक्ट्रॉनिक टोकन जारी करता है।
- इस टोकन मूल्य को सरकार के पूर्ण विश्वास और ऋण का समर्थन प्राप्त है।

ध्यान दें: कृपया ध्यान रखें कि क्रिप्टोकरेंसी (जैसे बिटकॉइन, डॉगकोइन आदि) एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है। वे समान नहीं हैं। उनके बीच बड़े अंतर हैं।

क्रिप्टोकरेंसी vs डिजिटल मुद्रा

यहां कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं –

- **विकेंद्रीकरण (Decentralization):** डिजिटल मुद्राएं केंद्रीकृत होती हैं, यानी इन्हें एक एकल संस्था, जैसे केंद्रीय बैंक, द्वारा नियंत्रित और जारी किया जाता है।
- **खुलापन (Openness):** क्रिप्टोकरेंसी में, आप सभी लेन-देन देख सकते हैं क्योंकि निर्देशिका (लेजर) को खुला रखा जाता है। यह कार्यक्षमता ब्लॉकचेन की एक अभिन्न विशेषता है, जहां प्रत्येक ब्लॉक में पिछले लेन-देन की जानकारी होती है। डिजिटल मुद्राओं में, कोई व्यक्ति पूरी लेन-देन श्रृंखला को दृश्य रूप से नहीं देख सकता।
- **कानूनी ढांचा (Legal Framework):** अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी के पास कोई कानूनी ढांचा नहीं होता, जबकि

पूंजीगत लाभ कर लगाने की पश्चिमी अवधारणा का पालन कर सकती है।

2. **डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना:** सरकार को पर्याप्त जागरूकता अभियान चलाने होंगे और लोगों को धोखाधड़ी के तरीकों की पहचान करने के बारे में जानकारी देनी होगी। इससे भारत का डिजिटल विभाजन कम होगा।
3. **पर्याप्त साइबर सुरक्षा विधियों का निर्माण:** राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा की शुरुआत से पहले, सरकार को कुछ महत्वपूर्ण चीजें बनानी होंगी, जैसे कि, किसी भी खतरे से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों का प्रशिक्षण। किसी की डिजिटल मुद्रा जारी करते समय, सत्यापित करते समय मूल्यांकित बुनियादी जानकारी की एक नीति बनाना।
4. **बैंक रन और विमध्यस्थता की सीमा को रोकना:** CBDC की व्यक्तिगत होल्डिंग्स पर सीमा यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि CBDC का उपयोग मुख्य रूप से भुगतान के लिए किया जाता है न कि बड़ी बचत के लिए। यह बैंकिंग प्रणाली के विमध्यस्थता की सीमा को भी कम करेगा।
5. **RBI द्वारा दो-स्तरीय दृष्टिकोण:** RBI एक नियामक संस्था है और वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। इसलिए, एक दो-स्तरीय दृष्टिकोण उपयोगी होगा जिसमें, **Tier 1 के तहत:** RBI अपनी मुद्रा का डिजिटल संस्करण बनाता है, और **Tier 2 के तहत:** मुद्रा का वितरण और CBDC वॉलेट का रखरखाव मौजूदा वित्तीय मध्यस्थों पर छोड़ दिया जाता है।

एक CBDC या एक राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा की शुरुआत निजी स्वामित्व वाली क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े विभिन्न खतरों को रोकती है और भारत को एक प्रगतिशील डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगी। लेकिन सरकार को इसे शुरू करने से पहले आवश्यक सुरक्षा उपाय बनाने होंगे।

अध्याय – 9

भारत में बैंकिंग - भाग I

भारत में बैंकिंग का इतिहास और विकास

- बैंकिंग शब्द की उत्पत्ति पश्चिमी दुनिया में हुई।
- भारत में बैंकिंग का सबसे पहला प्रमाण वैदिक सभ्यता के काल से मिलता है। उन दिनों, ऋणपत्र नामक ऋण विलेख प्रचलित थे जिन्हें ऋणपत्र या ऋणलेख्य कहा जाता था।
- बौद्ध, मौर्य और मुगल काल में विभिन्न प्रकार के उपकरण पाए गए।
- कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल के दौरान बैंकरों की उपस्थिति का उल्लेख है, जिन्हें "**आदेश**" के रूप में जाना जाता है जो वर्तमान समय के विनिमय बिल के समतुल्य हैं।
- भारत का पहला बैंक जिसे बैंक ऑफ हिन्दुस्तान कहा जाता है, 1770 में स्थापित किया गया था।

एक बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो जनता से जमा स्वीकार करता है और ऋण बनाता है। उधार देने की गतिविधियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी बाजारों के माध्यम से की जा सकती हैं।

तीन प्रेसीडेंसी बैंक

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टरों के तहत तीन प्रेसीडेंसी बैंक स्थापित किए गए थे - **बैंक ऑफ कलकत्ता (1806), बैंक ऑफ बॉम्बे (1840) और बैंक ऑफ मद्रास (1843)।** इन बैंकों ने कई वर्षों तक भारत में अर्ध-केंद्रीय बैंकों के रूप में काम किया।

इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया

- 1921 में, तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया।
- 1955 में, इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) कर दिया गया। इस प्रकार, SBI आज मौजूद बैंकों में भारत का सबसे पुराना बैंक है।

भारत में बैंकिंग वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी और विदेशी बैंकों के सह-अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है।

भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक

भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक इलाहाबाद बैंक है। इसे भारत के सबसे पुराने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी।

एक बैंक जिसमें कई शेयरधारक होते हैं, उसे संयुक्त-स्टॉक बैंक कहा जाता है।

भारतीयों के स्वामित्व/प्रबंधन वाले पहले बैंक

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1895 में लाहौर में हुई थी। PNB भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है।
- हालांकि, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी।
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भारत का पहला स्वदेशी बैंक कहा जाता है। इसके संस्थापक सर सोराबजी पोचखानवाला थे और इसके पहले अध्यक्ष सर फिरोजशाह मेहता थे।
- बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला भारतीय बैंक था जिसने 1946 में लंदन में भारत के बाहर एक शाखा खोली।

वर्ष	बैंक
1770	भारत का पहला बैंक 'बैंक ऑफ हिंदोस्तान' 1770 में स्थापित हुआ।
1861	ब्रिटिश सरकार ने भारत में 'पेपर करेंसी एक्ट' लागू किया।
1865	भारत का सबसे पुराना जॉइंट-स्टॉक बैंक 'इलाहाबाद बैंक' स्थापित हुआ।
1881	अवध कमर्शियल बैंक, भारतीय बोर्ड द्वारा प्रबंधित सीमित देयता वाला भारत का पहला बैंक, फैजाबाद में स्थापित किया गया था।
1895	'पंजाब नेशनल बैंक' स्थापित हुआ। यह पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था।
1911	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, स्थापित किया गया था। इसे पहला वास्तव में स्वदेशी बैंक कहा जाता था।
1921	तीन प्रेसीडेंसी बैंक - बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया।
1935	भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ।
1949	भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ।
1949	'बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट' लागू किया गया।
1955	'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया' का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसे बाद में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का नाम दिया गया।
1969	14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।
1980	7 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपये से अधिक थी।
सुधार	बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए समितियाँ बनाई गईं - नारसिंहम-I (1991), M नारसिंहम-I (1997), डॉ. रघुराम राजन समिति (2007) और P J नायक समिति (2014)।

वित्तीय मध्यस्थ (Financial Intermediaries)

- वे संस्थाएँ जो बचतकर्ताओं (अधिशेष) से उपयोगकर्ताओं (घाटा) के बीच धन का प्रवाह करती हैं, उन्हें वित्तीय मध्यस्थ कहा जाता है।
- ये बचतकर्ताओं (उधारकर्ता, निवेशक, गृहस्थ) और उधारकर्ताओं (उधमी, व्यापारिक फर्म) के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।
- ऐसे वित्तीय मध्यस्थों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: (1) औपचारिक (2) अनौपचारिक

पैरामीटर	औपचारिक	अनौपचारिक
परिभाषा	वित्त की औपचारिक प्रणाली केंद्रीय बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।	वित्त की अनौपचारिक प्रणाली केंद्रीय बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त नहीं है।
संस्थान	वाणिज्यिक और विकास बैंक - RRB, डाकघर बैंक आदि।	बचत संग्राहक, बचत और ऋण संघ, और साहूकार।
मुख्य ग्राहक	बड़े व्यवसाय, वेतनभोगी कर्मचारी, छोटे और मध्यम उद्यम।	अनौपचारिक वित्त का लाभ उठाने वाले लोग या तो ग्रामीण गरीब हैं या स्व-नियोजित लोग।

वित्तीय मध्यस्थों के प्रकार

FI (वित्तीय संस्थान)

1. **बैंक**
    - **वाणिज्यिक** - सार्वजनिक, निजी, विदेशी, RRB (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)
    - **सहकारी** - शहरी, राज्य, PACS (प्राथमिक कृषि साख समितियाँ)
2. **NBFI (गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान)**
    - AIFI (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान)
    - EXIM (भारतीय निर्यात-आयात बैंक)
    - NHB (राष्ट्रीय आवास बैंक)
    - SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक)
    - NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)
    - प्राथमिक डीलर
    - NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ)

मौद्रिक और बैंकिंग कार्यों के वैकल्पिक दृष्टिकोण के अनुसार, बैंक मध्यस्थ नहीं बल्कि 'मौलिक धन सृजन' संस्थान हैं, जबकि कथित 'मध्यस्थों' की श्रेणी के अन्य संस्थान केवल निवेश कोष हैं।

वित्तीय मध्यस्थों के लाभ

1. जोखिम फैलाना
2. सुविधा
3. वित्तीय विशेषज्ञ

4. पैमाने की अर्थव्यवस्था
5. सुरक्षित निवेश
6. अधिक तरलता

संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर FI का प्रभाव

- FI प्रणाली में पैसे का संचार करने में मदद करते हैं।
- पैसे की उच्च गति सुनिश्चित करता है।
- वे बचत की आदत को बढ़ावा देते हैं।
- एक जरूरतमंद व्यवसायी को आसानी से ऋण मिल जाएगा।
- नए व्यवसायों को बढ़ावा देता है, मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करता है, अधिक कर्मचारियों को काम पर रखता है, वस्तुओं/सेवाओं का उत्पादन बढ़ाता है।

❖ **भारत में बैंक**

भारत में बैंकों के प्रकार

1. केंद्रीय बैंक
2. अनुसूचित बैंक

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

- **सार्वजनिक क्षेत्र** - SBI समूह, राष्ट्रीयकृत बैंक, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
- **निजी क्षेत्र** – नए, पुराने
- विदेशी
- RRB (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

अनुसूचित सहकारी बैंक

- **ग्रामीण** - प्राथमिक साख समितियाँ
- **शहरी** - जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक

3. गैर-अनुसूचित बैंक - स्थानीय क्षेत्र के बैंक, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

RBI: उत्पत्ति और विकास

- RBI की स्थापना से पहले, एक केंद्रीय बैंक के कार्यों को वस्तुतः इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता था। RBI ने 1 अप्रैल, 1935 से अपना परिचालन शुरू किया।
- यह RBI अधिनियम 1934 के माध्यम से स्थापित किया गया था, इसलिए इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में भी जाना जाता है। इसी तरह, SBI भी एक वैधानिक निकाय है जो SBI अधिनियम 1955 से अपनी वैधता प्राप्त करता है।
- RBI की शुरुआत सरकार के स्वामित्व वाले बैंक के रूप में नहीं बल्कि एक निजी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में हुई थी।
- स्वतंत्रता के बाद, सरकार ने रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण) अधिनियम, 1948 पारित किया और उचित मुआवजा देने के बाद निजी शेयरधारकों से RBI को अपने कब्जे में ले लिया।
- इस प्रकार, 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1 जनवरी, 1949 से, RBI ने सरकार के स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया।

समयरेखा

वर्ष	घटना
1926	भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन (हिल्टन यंग कमीशन) ने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की। इस आयोग के आधार पर, RBI अधिनियम, 1934 पारित किया गया था।
1934	RBI विधेयक पारित हुआ और गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त हुई।
1 अप्रैल 1935	रिज़र्व बैंक ने पाँच करोड़ रुपये की चुकता पूंजी के साथ एक निजी शेयरधारक बैंक के रूप में भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया।
1949	भारत सरकार ने रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तांतरण) अधिनियम, 1948 के तहत रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया।

- RBI देश की सर्वोच्च मौद्रिक और बैंकिंग प्राधिकरण है और भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है।
- इसे **'रिज़र्व बैंक'** कहा जाता है क्योंकि यह सभी वाणिज्यिक बैंकों का आरक्षित रखता है।
- RBI का मूल मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में, इसे शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

- • स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत सरकार बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 लेकर आई।
- • इस अधिनियम को बाद में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1949 में बदल दिया गया।
- • इसके अलावा, 1965 के बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम ने भारत के केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापक शक्तियां दीं।

RBI की संस्थागत संरचना

RBI

- आधिकारिक निदेशक – गवर्नर, उप-गवर्नर (अधिकतम चार)
- गैर-आधिकारिक निदेशक - नामित (10+2), अन्य (चार स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक से एक)
- केंद्रीय निदेशक मंडल RBI में शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। यह आधिकारिक और गैर-आधिकारिक निदेशकों से बना है।
- गवर्नर और डिप्टी गवर्नर आधिकारिक निदेशक होते हैं।
- एक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं (RBI अधिनियम 1934 की धारा-8 के अनुसार); इसलिए RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में आधिकारिक निदेशकों की अधिकतम संख्या पाँच है।

- गवर्नर और डिप्टी गवर्नरों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सेवा का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होता है और इसे फिर से नियुक्त किया जा सकता है।
- इसके अलावा, RBI में 16 गैर-आधिकारिक निदेशक हैं।
- उनमें से, चार दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में स्थित स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस प्रकार भारत के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- शेष 12 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित किया जाता है। इन 12 व्यक्तित्वों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता है।
- केंद्रीय निदेशक मंडल हर साल कम से कम 6 बैठकें करता है। जिनमें से, प्रत्येक तिमाही (हर 3 महीने) में कम से कम 1 बैठक आयोजित की जाती है।
- हालांकि, आमतौर पर केंद्रीय बोर्ड की समिति हर हफ्ते (बुधवार) मिलती है।

RBI के गवर्नर

- **नियुक्ति** - कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (FSRASC) द्वारा किए गए प्रस्ताव के बाद नियुक्ति।
- **कार्यकाल** - RBI अधिनियम की धारा 8 (4) के अनुसार, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर ऐसे कार्यकाल के लिए पद धारण करेंगे जो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा जैसा कि केंद्र सरकार उन्हें नियुक्त करते समय तय कर सकती है।
- **पुनः नियुक्ति** - वे पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
- **योग्यता** - RBI अधिनियम गवर्नर के लिए किसी विशिष्ट योग्यता का प्रावधान नहीं करता है।
- **निष्कासन** - गवर्नर को केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है।

RBI के वर्तमान गवर्नर - संजय मल्होत्रा

RBI की सहायक कंपनियाँ

- जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC)
- भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL)
- रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT)
- इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज (IFTAS)।

RBI में सहायक निकाय - वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (BFS) और भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड (BPSS); ये दोनों RBI गवर्नर द्वारा संचालित हैं।

प्रेस की संख्या	**चार छपाई प्रेस बैंक नोट छापते और आपूर्ति करते हैं**
स्थान	नासिक - महाराष्ट्र, देवास - मध्य प्रदेश, मैसूर - कर्नाटक, सालबोनी - पश्चिम बंगाल
सरकार के स्वामित्व में	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रेस भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SPMCIL) के स्वामित्व में हैं। SPMCIL आर्थिक मामलों के विभाग (MoF) के तहत एकमात्र PSU है
RBI के स्वामित्व में	कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के प्रेस भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) के स्वामित्व में हैं, जो RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
सिक्के	भारत सरकार सिक्कों का जारी करने वाला प्राधिकरण है और मांग पर रिज़र्व बैंक को सिक्कों की आपूर्ति करता है। RBI केंद्र सरकार की ओर से सिक्कों को प्रचलन में लाता है।

कार्य

1. मुद्रा निर् जारी करने वाला बैंक
   - मुद्रा जारी करना RBI का विशेष अधिकार है।
   - 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर सभी नोट RBI द्वारा जारी किए जाते हैं।
   - यह पुरानी क्षतिग्रस्त मुद्राओं का विनिमय या नष्ट भी करता है।
   - 1 रुपये के नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं और RBI द्वारा परिचालित किए जाते हैं।
2. विदेशी विनिमय का संरक्षक और प्रबंधक
   - RBI विदेशी मुद्रा (अर्थात विदेशी मुद्रा) रखता है जो देश में आती है।
   - यह एक निश्चित सीमा तक विदेशी विनिमय दर को भी स्थिर रखता है
3. सरकार का बैंकर और ऋण प्रबंधक
   - यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के बैंकर के रूप में कार्य करता है (जम्मू और कश्मीर और सिक्किम को छोड़कर)।
   - यह सरकारों की जमा राशि रखता है और सरकारों को उधार देता है।
   - RBI सरकार की ओर से सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी करके उधार और उधार लेने का कार्य करता है।
   - हालांकि RBI सिक्किम और जम्मू और कश्मीर का बैंकर नहीं है, यह कुछ हद तक उनके सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है।
4. बैंकों का बैंकर
   - यह सभी बैंकों का बैंकर है।
   - यह बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (CRR) जैसे भंडार अपने पास रखता है।
   - यह बैंकों को गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के एवज में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
   - यह विनिमय पत्रों को पुनः छूट देता है।
   - आमतौर पर बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित कॉल मनी मार्केट के माध्यम से आपस में धन उधारते और उधार देते हैं।

- RBI बैंकों को पर्याप्त धन मुहैया कराता है और अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता के रूप में जाना जाता है।

5. **मुद्रा प्रबंधन** - मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रक, मौद्रिक नीति बनाता है, ऋण नियंत्रण आदि।
6. **वित्तीय विनियामक** - वाणिज्यिक बैंकों, ऋण सूचना कंपनियों, RRBs, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, NBFC आदि के लिए।
7. **प्रतिनिधि भूमिका** - RBI सरकार का प्रतिनिधित्व करता है जैसे IMF और विश्व बैंक के सदस्य के रूप में।
8. **केंद्रीय समाशोधन और लेखा निपटान** - चूंकि RBI वाणिज्यिक बैंकों से नकद भंडार रखता है, इसलिए यह उनके विनिमय पत्रों को आसानी से पुनः छूट देता है।
9. **विकासात्मक भूमिका** - विभिन्न प्रकार के विकासात्मक और प्रचारात्मक कार्यों का प्रदर्शन करना जिसके तहत इसने IDBI, SIDBI, NABARD, NHB आदि जैसी संस्थाओं की स्थापना की।
10. **प्रचारात्मक भूमिकाएं** - उपभोक्ता संरक्षण, लोकपाल, PSL मानदंडों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, 25% ग्रामीण शाखा आवश्यकताएं आदि।

RBI के क्रेडिट और मौद्रिक नीति शासन में नई पहल

- द्विमासिक मौद्रिक नीति चक्र में संक्रमण - डिसइन्फ्लेशन के लिए ग्लाइड पाथ की स्वीकृति (उर्जित पटेल समिति रिपोर्ट की सिफारिश पर)। इसके तहत, CPI (C) को RBI द्वारा मौद्रिक प्रबंधन के लिए "हेडलाइन इन्फ्लेशन" के रूप में उपयोग किया जाता है।
- मौद्रिक नीति ढांचा (2015) स्थापित किया गया है - इस संबंध में भारत सरकार और RBI के बीच फरवरी 2015 के अंत में एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। इस ढांचे के तहत, RBI को "मूल्यवृद्धि" को 4 प्रतिशत पर लक्षित करने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें +/- 2 प्रतिशत का उतार-चढ़ाव हो सकता है (CPI-C का)।
- मौजूदा रेपो मार्ग के अलावा, तीन अवधि समूहों के लिए टर्म रेपो की शुरुआत की गई है - 7, 14 और 28 दिन - यह नीति के संचरण और ऋण बाजार में स्थिरता सुधारने के उद्देश्य से किया गया कदम है।
- संघीय बजट 2016-17 के अनुसार, RBI व्यक्तियों को सरकार के सुरक्षा बाजार में भाग लेने की अनुमति देगा (जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे USA में है)।
- RBI धीरे-धीरे बैंकों के लिए रातोंरात तरलता (निश्चित रेपो दर पर) की पहुंच को कम कर रहा है, और बैंकों को टर्म रेपो पर अपनी निर्भरता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

RBI के आय और व्यय के स्रोत

आय	व्यय
विदेशी मुद्रा संपत्तियों से आय	मुद्रा की छपाई
रुपये-मूल्यवर्ग के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज	कर्मचारी व्यय
वाणिज्यिक बैंकों को रातोंरात उधार पर ब्याज।	वाणिज्यिक बैंकों को दिया गया कमीशन
केंद्र और राज्य सरकारों के उधार को संभालने पर प्रबंधन कमीशन	प्राथमिक डीलरों को कमीशन

RBI की परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

देयताएँ	परिसंपत्तियाँ
जनता के पास मौजूद मुद्रा	विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित वॉल्ट कैश	बिल खरीद और छूट
सरकारी प्रतिभूतियाँ	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संपार्श्विक
अन्य देयताएँ	ऋण और अग्रिम, सोने की सिक्के और बुलियन

RBI की स्वतंत्रता

- RBI अधिनियम 1934 की धारा 7 के तहत, केंद्रीय सरकार समय-समय पर RBI को ऐसे निर्देश दे सकती है, जिन्हें वह बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद जनहित में आवश्यक समझे। इसके अलावा, RBI की स्वायत्तता को अनिवार्य करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
- RBI को न केवल मौद्रिक नीति तैयार करने का अधिकार प्राप्त है, बल्कि सभी बैंकों के कार्यों की निगरानी करने का भी अधिकार प्राप्त है।
- अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए, RBI की कार्यप्रणाली में स्वायत्तता अनिवार्य है।
- हालाँकि, यह कई बार चुनौती दी जा चुकी है क्योंकि बैंक और सरकार के बीच अधिक शक्ति पाने के लिए लगातार संघर्ष होता है।

RBI की घटती स्वायत्तता के कारण

- गैर-निष्पादित आस्तियों (NPAs) की वृद्धि की जाँच करना।
- RBI द्वारा अपनाई गई सख्त मौद्रिक नीति के कारण अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी।
- बैंकिंग प्रणाली को साफ़ करने के लिए RBI द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपाय जिन्हें सरकार द्वारा बहुत सकारात्मक रूप से नहीं देखा जाता है।
- RBI की असंभव त्रिमूर्ति - पूंजी गतिशीलता, विनिमय दर लचीलापन और मौद्रिक स्वायत्तता।
- सरकार के अल्पकालिक लोकलुभावन एजेंडे और RBI द्वारा ली गई मूल्य स्थिरता के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के बीच टकराव।
- एक महत्वपूर्ण सीमा यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के खिलाफ कार्रवाई की पूरी गुंजाइश शुरू करने में रिज़र्व बैंक वैधानिक रूप से सीमित है।

खाद्य सब्सिडी, खाद उर्वरक (यूरिया > अन्य), ईंधन (एलपीजी > केरोसिन), ऋण पर ब्याज सब्सिडी (किसानों के लिए, MSME, सस्ती आवास, LIC वय-वंदना योजना आदि)।
अन्य जैसे मूल्य स्थिरीकरण कोष, कपास और जूट आदि।

5. **रक्षा के राजस्व व्यय:**
   जैसे सैनिकों के वेतन, टैंकों के लिए ईंधन।
6. **सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन:**
   पिछले 3 वर्षों में इस व्यय में वृद्धि हुई है।
7. **आर्थिक सेवाओं से संबंधित राजस्व व्यय:**
   जैसे कृषि, ऊर्जा, परिवहन, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
8. **सामाजिक सेवाओं से संबंधित राजस्व व्यय:**
   जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा।
9. **प्रशासनिक मशीनरी पर खर्च:**
   जैसे पुलिस, जेल, विदेश मंत्रालय, चुनाव, संसद, न्यायपालिका।
10. **संविधानिक प्राधिकरणों के राजस्व व्यय:**
    जैसे चुनाव आयोग, न्यायपालिका आदि।

अध्याय – 17

राजस्व व्यय और सब्सिडी (REVENUE EXPENDITURE AND SUBSIDIES)

कर (Tax) (बजट 2020 में ₹ ~16 लाख करोड़)

- कर राज्य द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य योगदान है।
- कर का भुगतान करने से इनकार करना दंडनीय है।
- कर करदाता को विशिष्ट और प्रत्यक्ष वस्तुओं/सेवाओं का वादा नहीं करता है।

सब्सिडी (Subsidies) (बजट 2020 में ₹ ~ 2.6 लाख करोड़)

- सब्सिडी सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या फर्म को कुछ प्रकार के बोझ को कम करने के लिए दिया जाने वाला लाभ है। कोई व्यक्ति सब्सिडी स्वीकार करने से इनकार कर सकता है, उसे दंडित नहीं किया जाएगा।
- एक विशिष्ट लाभ का वादा किया जाता है।

सब्सिडी के प्रकार (Types of subsidies)

प्रकार	उदाहरण
सीधे नकद (या बैंक ट्रांसफर) में दी गई	पीएम किसान ₹6000/वर्ष तीन किस्तों में, एलपीजी पहल लगभग ₹200 प्रति सिलेंडर।
वस्तु के रूप में दी गई	गरीब बच्चों को मुफ्त स्कूल बैग, यूनिफार्म और किताबें, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त बीमा।
अप्रत्यक्ष सब्सिडी	सरकारी कॉलेजों में सस्ती फीस, सस्ता केरोसिन, सस्ती यूरिया, सस्ती फसल बीमा प्रीमियम आदि। यहां सरकार किसी संगठन को कुछ पैसा देती है ताकि वे लाभार्थी को सस्ते दरों पर वस्त्र/सेवाएँ प्रदान कर सकें
नियामक सब्सिडी	उदाहरण: यदि राज्य विद्युत नियामक आयोग कंपनियों को निर्देश देता है कि किसानों को दी जाने वाली बिजली ₹ "निर्दिष्ट" प्रति यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
खरीद सब्सिडी	उदाहरण: FCI किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न खरीदता है।
ब्याज सब्सिडी/सबवेंशन	सरकार कृषि, MSME और किफायती आवास ऋणों पर "निर्दिष्ट%" ब्याज देती है।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

सब्सिडी का प्रभाव

- **गुणवत्ता वाले सामान (Merit Goods)** – स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, एलपीजी, सौर पैनल, पवन चक्कियाँ आदि। यहां सब्सिडी सकारात्मक बाहरी प्रभावों (positive externalities) को बढ़ा सकती है। सस्ती एलपीजी के कारण गरीब लोग लकड़ी जलाने का उपयोग नहीं करते। इससे अधिक पेड़ उगेंगे और इनडोर प्रदूषण कम होगा।
- डीजल और केरोसिन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर्यावरण पर नकारात्मक बाहरी प्रभाव उत्पन्न करती है।
- उद्योगों को दी जाने वाली यूरिया सब्सिडी किसानों के लिए यूरिया को सस्ता बनाती है। इससे अत्यधिक खपत हुई, जिससे मिट्टी और जल प्रदूषण, शैवाल वृद्धि (algae-blooms) हुई।
- **सब्सिडी लीक:** जब भूत/प्रॉक्सी लाभार्थी (अस्तित्वहीन व्यक्ति जिन्हें भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा खड़ा किया गया) और अव्यक्त (धनी) लोग सब्सिडी प्राप्त कर रहे होते हैं।

सब्सिडी वितरण पर पिछले आर्थिक सर्वेक्षण

आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15	हमें सब्सिडी के रिसाव को कम करने के लिए जन धन, आधार, मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति का उपयोग करना चाहिए।
आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) हर मामले में रामबाण नहीं हो सकता, क्योंकि घर के पुरुष DBT-धन को शराब और तम्बाकू पर बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए, कुछ मामलों में, बायोमेट्रिक रूप से प्रमाणित भौतिक उठाव (BAPU) तंत्र बेहतर होगा, यानी लाभार्थी अनाज/उर्वरक की दुकान पर जाता है और सब्सिडी वाले सामान खरीदने के लिए अपने आधार और उंगलियों के निशान का उपयोग करता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17	वर्तमान सब्सिडी वितरण तंत्र दो त्रुटियों से ग्रस्त है: **समावेश त्रुटि (Inclusion Error):** गैर-गरीब (=समृद्ध लोग) सब्सिडी का ~40% प्राप्त कर रहे हैं। **बहिष्करण त्रुटि (Exclusion Error):** भ्रष्टाचार के कारण वास्तविक गरीबों में से 50% को सब्सिडी नहीं मिल रही है। इसलिए सभी प्रकार की सब्सिडी को समाप्त करना और लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे एक निश्चित राशि जमा करना बेहतर है ताकि उसे खुले बाजार से सामान/सेवाएं खरीदने में मदद मिल सके = सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI)।

आर्थिक सर्वेक्षण 2019: सब्सिडी बिल को कम करने के लिए 'व्यवहार अर्थशास्त्र' का उपयोग करें

सरकार के सब्सिडी बोझ को कम करने के लिए, गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के परिवारों को स्वेच्छा से अपनी LPG सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर पूर्वी राज्यों ने सब्सिडी छोड़ने की उच्च दर दिखाई है। निम्नलिखित सुधार आवश्यक हैं:

- लोगों की यथास्थिति के साथ चलने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इसलिए, LPG पंजीकरण फॉर्म में 'डिफ़ॉल्ट टिक विकल्प' 'मैं सब्सिडी छोड़ना चाहता/चाहती हूँ' होना चाहिए, इसलिए एक व्यक्ति सब्सिडी लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प को अनटिक करने के लिए 'मजबूर' होगा।
- इसी तरह, आयकर फॉर्म में पूर्व-टिक वाले विकल्पों के साथ अतिरिक्त फ़ील्ड होने चाहिए जैसे 'मैं LPG सब्सिडी छोड़ना चाहता/चाहती हूँ'।
- ऑनलाइन/SMS-आधारित 'सब्सिडी छोड़ने की प्रक्रिया' त्वरित और परेशानी मुक्त होनी चाहिए। इसमें कुछ मिनटों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। क्योंकि औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रत्येक अतिरिक्त मिनट से इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि व्यक्ति प्रक्रिया के बीच में ही छोड़ दे।
- लोग सकारात्मक रूप से कार्य करते हैं जब वे दूसरों को सकारात्मक रूप से कार्य करते हुए देखते हैं, और विशेष रूप से तब जब वे ऐसे व्यक्तियों से जुड़ सकें। इसलिए, एक ऑनलाइन "सम्मान की सूची" में उनके क्षेत्र के उन अन्य लोगों के नाम/फोटो/सोशल मीडिया-प्रोफ़ाइल दिखाए जाने चाहिए जिन्होंने सब्सिडी छोड़ दी।
- "अमीर लोग सब्सिडी छोड़कर गरीबी उन्मूलन में मदद कर रहे हैं" को उजागर करने वाले विज्ञापन।
- जब लोग सामाजिक संदेश वाली फिल्म (जैसे पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा आदि) देख रहे हों, तो उसमें लोगों से पूर्ण/आंशिक सब्सिडी छोड़ने के लिए कहने वाले विज्ञापन होने चाहिए।
- एक बार जब कोई व्यक्ति सब्सिडी छोड़ देता है, तो उसे उसके कार्य से लाभान्वित होने वाले गरीब लोगों की तस्वीरें/या एक लाभार्थी का 'धन्यवाद' कहता हुआ एक वीडियो दिखाया जाना चाहिए।

राजस्व व्यय और 7वां वेतन आयोग

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा स्थापित। पहला वेतन आयोग: श्रीनिवास वरदाचारी (1946)। 7वां वेतन आयोग – (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति ए.के. माथुर (2014)। इसकी सिफारिशें । जनवरी 2016 से प्रभावी हुईं। मुख्य विशेषताएं थीं -

- वेतन बैंड और ग्रेड पे की पिछली प्रणाली के बजाय "वेतन मैट्रिक्स" की नई प्रणाली।

Dear Aspirants, here are the our results in differents exams (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न, 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न, 150 में से)

UP Police Constable 2024 - http://surl.li/rbfyn (98 प्रश्न, 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk8S6W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

whatsapp https://wa.link/6bx90g 1 web.- https://shorturl.at/SgSVX

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

whatsapp https://wa.link/6bx90g 2 web.- https://shorturl.at/5gSVX

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 563+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
	Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

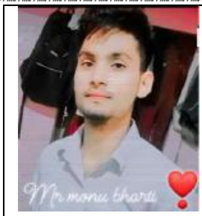	**MONU S/O KAMTA PRASAD**	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
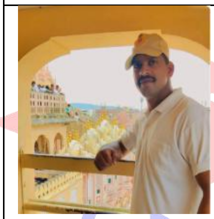	**Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel**	Rac batalian	729141135	Dis.-Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota
	Sanjay	Haryana PCS	96379	Jind (Haryana)

And many others……

Click on the below link to purchase notes

WhatsApp करें - https://wa.link/6bx90g

Online Order करें - https://shorturl.at/5gSVX

Call करें - 9887809083

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO